

डेटा संरक्षण नियम

केंद्र सरकार ने डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण नियम 2025 का मसौदा जारी कर दिया है। मसौदा नियमों में बच्चों के सोशल मीडिया आकड़ों को खोलने के लिए अभिभावकों की अनिवार्य और प्रमाणित सहमति लेने का प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि मसौदा नियम परामर्श के लिए खुले हैं। उन्होंने लोगों से अपने विचार व्यक्त करने को भी कहा है। डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अगस्त 2023 में मंजूरी दी थी। इन नियमों के बारे में व्यक्त की गई कोई भी प्रतिक्रिया गोपनीय रखी जाएगी ताकि लोग अपने विचार स्वतंत्र रूप से साझा कर सकें। मसौदा नियमों पर अपने विचार माय गव पोर्टल के माध्यम से 18 फरवरी तक व्यक्त किये जा सकते हैं।

राज्यपाल

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि नौतोड़ भूमि प्रस्ताव पर राजभवन ने कुछ आपत्तियां लगाई हैं जिनका जवाब सरकार से मांगा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से अब तक इस संबंध में कोई जवाब नहीं मिला है। राज्यपाल ने कहा कि वे नौतोड़ के खिलाफ नहीं हैं मगर हर कार्य नियमों के अनुसार किया जाएगा।

इस बीच राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि यह विधेयक दो साल से राजभवन में लम्बित है। उन्होंने कहा कि वे इस मामले पर राज्यपाल से कई बार मुलाकात कर चुके हैं। राजस्व मंत्री ने कहा कि राज्यपाल के किन्नौर दौरे के दौरान भी विभिन्न प्रतिनिधी मंडलों ने मुलाकात कर इस प्रस्ताव को स्वीकृति देने की गुहार लगाई थी।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज जुब्बल-कोटखाई, नावर विधानसभा क्षेत्र के तहत गुम्मा में सी. ए. स्टोर का उद्घाटन करेंगे। वे कोटखाई में मिनी सचिवालय भवन के उद्घाटन के अलावा ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री फागू में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह का उद्घाटन भी करेंगे।

पानी घोटाला

शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में हुए कथित पानी घोटाले में जल शक्ति विभाग ने प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई करते हुए विभाग के 10 जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा विभाग ने संबंधित ठेकेदार को भी ब्लैकलिस्ट करने के आदेश जारी किए हैं।

बल्क ड्रग पार्क

ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र के पोलियाँ गांव में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क के लिए पानी की व्यवस्था पर 66 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी। जल शक्ति विभाग के अनुसार यह कार्य तीन चरणों में पूरा किया जाएगा और इसमें पेयजल आपूर्ति के अलावा वर्ष जल संग्रहण कार्य शामिल होंगे। बल्क ड्रग पार्क परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश सरकार द्वारा बिजली, सड़कों और जलापूर्ति योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। इस पार्क पर केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा 2 हजार करोड़ रुपये का निवेश कर दवाइयाँ बनाई जाएंगी जिससे भारत को विदेशों से जरूरी दवाओं का आयात न करना पड़े।

प्रशिक्षण

प्रदेश में शिवा प्रोजेक्ट के तहत बागवानी गतिविधियों को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए कांगड़ा, मण्डी, सिरमौर और हमीरपुर के उद्यान व जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के एक दल ने राष्ट्रीय जल अकादमी पुणे में प्रशिक्षण हासिल किया। एचपी शिवा परियोजना के निदेशक डॉक्टर देवेन्द्र ठाकुर ने बताया कि इन अधिकारियों को 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक लघु सिंचाई प्रणाली में सॉफ्टवेयर डिजाइन और जल प्रबंधन सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई।

मौसम

राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादल छाए हैं। बीते कुछ दिनों में मौसम के साफ रहने से दिन के तापमान में मामूली वृद्धि हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी व वर्षा होने का अनुमान लगाया है।